

भाग एक: अर्थव्यवस्था - समीक्षा और संभावनाएं

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

1.1 वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक विस्तार स्थिर गति से होता रहा, बावजूद इसके कि भू-राजनीतिक तनाव, भू-आर्थिक विखंडन, बढ़े हुए व्यापार तनाव और बढ़े हुए लोक ऋण के बीच संवृद्धि असमान रही। 2022 में की गई मौद्रिक सख्ती के विलंबित प्रभाव के साथ-साथ वस्तुओं की कीमतों में नरमी आने और आपूर्ति स्थिति सुगम बनने के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में कम हुई। तथापि, प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में सेवा मुद्रास्फीति निरंतर बनी रहने से इन देशों में मुद्रास्फीति कम होने की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है। प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने 2024 के मध्य तक उदार मौद्रिक नीति रुख अपनाया जिससे वित्तीय स्थितियां व्यापक रूप से सुगम बनीं। फिर भी, नीतिगत बदलावों, भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और प्रौद्योगिकीय शेरों के बढ़े हुए मूल्यांकन के कारण वर्ष के दौरान वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। भू-राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितता के निरंतर बने रहने के बावजूद पण्य व्यापार में धीरे-धीरे सुधार हुआ। बढ़ी हुई भू-आर्थिक और नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में पूंजी प्रवाह अस्थिर रहा।

1.2 वर्ष 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की संवृद्धि वैश्विक व्यापार के अति संरक्षणवाद, बढ़ती नीतिगत अनिश्चितता और चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण न केवल 3.7 प्रतिशत के अपने ऐतिहासिक औसत (2000-19) से नीचे रहने की संभावना है बल्कि 2024 के 3.3 प्रतिशत की संवृद्धि से भी कम

हो सकती है। अवस्फीतिकारी स्थिति जारी रहने की उम्मीद है लेकिन उसकी गति धीमी रहेगी, और ईएमई की तुलना में ईई के अपने लक्ष्य तक पहले पहुंचने की संभावना है। तदनुसार, कई केंद्रीय बैंकों ने, बढ़ते व्यापार तनावों, मंडराती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन जोखिमों के प्रति सतर्क रहते हुए एक नरम चक्र की ओर रुख किया है। नीति निर्माताओं के सामने वित्तीय और समष्टि आर्थिक स्थिरता की रक्षा करते हुए संवृद्धि को समर्थन देने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को उपयुक्त रूप से निर्धारित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य है।

1.3 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2024-25 के दौरान, चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक वातावरण के बीच, समुत्थानशीलता प्रदर्शित की, जो मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचों और सक्रिय नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित है। वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति कम हो गई और लक्ष्य से नीचे चली गई। वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ बैंक और गैर-बैंक तुलनपत्रों, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और पूंजीगत बफर के कारण लचीला और मजबूत बना रहा; जिससे ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में हो सकी। राजकोषीय मोर्चे पर, बेहतर कर राजस्व प्राप्ति के चलते, केंद्र सरकार ने व्यय की गुणवत्ता में सुधार पर बल देते हुए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रयास जारी रखे। पूंजी प्रवाह अस्थिर रहने के बावजूद चालू खाता घाटा (सीएडी) मामूली रहने और विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त रहने से बाह्य क्षेत्र सुदृढ़ रहा।

* : जहां भी सूचना उपलब्ध है इस अध्याय को मार्च 2025 से आगे अद्यतन किया गया है।

1.4 वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी, जिसे निजी खपत में वृद्धि, बैंकों और कॉर्पोरेट के स्वस्थ तुलनपत्रों, सुगम वित्तीय स्थितियों और पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर द्वारा समर्थन प्राप्त है। आपूर्ति शृंखला के दबावों में कमी, वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में नरमी और सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून की संभावना के आधार पर उच्च कृषि उत्पादन 2025-26 में मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के लिए अच्छा संकेत है। अन्य बातों के अलावा, व्यापार शुल्क नीतियों के निर्धारणों में बढ़ती अनिश्चितता के मद्देनजर वैश्विक वित्तीय बाजारों की अति अस्थिर स्थिति के कारण वित्तीय बाजार उतार-चढ़ाव के छिटपुट दौर से गुजर सकता है। निर्यात क्षेत्र को बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, स्वावलंबी बनने वाली नीतियों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच संभावित टैरिफ-युद्ध के जोखिम के चलते कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, अमेरिका, ओमान, पेरू और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ बातचीत के तहत किए गए नए व्यापार सौदों के साथ-साथ 14 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमन्य व्यापार समझौतों (पीटीए) में भारत की भागीदारी व्यापार बढ़ाने में मदद कर सकती है। सुदृढ़ सेवा निर्यात और आवक विप्रेषण के कारण सीएडी स्थिति अनुकूल बने रहने की संभावना है, जो 2025-26 में प्रमुख रूप से नियंत्रण में होगी।

2. वर्ष 2024-25 का मूल्यांकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.5 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार¹, कमजोर निवेश, धीमी उत्पादकता वृद्धि, और उच्च ऋण स्तर जैसी संरचनात्मक चुनौतियों के कारण, वैश्विक संवृद्धि 2024 में 3.3 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 3.5 प्रतिशत) थी और 3.7

प्रतिशत के ऐतिहासिक औसत (2000-19) से नीचे रही। इसके अलावा, आर्थिक गतिविधियों की गति कुछ एशियाई और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक संवृद्धि में नरमी, लंबे भू-राजनीतिक तनाव और चीन के उपभोग मांग और संपत्ति बाजार में सुस्त वापसी से प्रभावित हुई। वैश्विक मुद्रास्फीति 2023 के 6.6 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.7 प्रतिशत हो गई, जो क्रमिक रूप से की गई मौद्रिक सख्ती और आपूर्ति शृंखला बाधाओं में आई कमी के प्रभाव को परिलक्षित करती है। लेकिन वह अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर से ऊपर बनी हुई है, जिसका एक बड़ा कारण है सेवा क्षेत्र में लगातार मूल्य दबाव।

1.6 वैश्विक पण्य व्यापार² की मात्रा में, आपूर्ति शृंखला के दबावों में कमी के कारण, 2024 में 2.9 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जबकि 2023 में इसमें 1.0 प्रतिशत की गिरावट आई थी। तथापि, भू-आर्थिक विखंडन और प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों का प्रतिकूल असर वैश्विक व्यापार प्रवाह पर जारी रहा। महामारी का प्रकोप कम हो जाने पर यात्रा व्यय में निरंतर बहाली आने और डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं की मांग बनी रहने से सेवा व्यापार ने सुदृढ़ता प्रदर्शित की।

1.7 मुद्रास्फीति के धीरे-धीरे लक्ष्य स्तरों के निकट आने से प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक वित्तीय स्थितियां काफी हद तक उदार बनी रहीं, जो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधात्मक नीति में कमी की ओर बदलाव को दर्शाती हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल 2024 की पहली छमाही में नरम रहे किंतु वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान नए सिरे से मुद्रास्फीति चिंताओं और प्रमुख केंद्रीय बैंकों के अलग-अलग मौद्रिक नीति दिशापथों के चलते सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल में फिर से वृद्धि हुई। सामान्य रूप से वैश्विक दर में कटौती चक्र के बीच उभरते बाजार और विकासशील

¹ वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2025, आईएमएफ।

² ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक अपडेट, अप्रैल 2025, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)।

अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल कम हुए। अमेरिकी डॉलर पूरे वर्ष मजबूत रहा, जिसके परिणामस्वरूप कई आई और ईएमई मुद्राओं पर अधोगामी दबाव पड़ा। वैश्विक इक्विटी बाजारों में, मूल्यांकनों के बढ़ने, परस्पर भिन्न स्वरूप की मौद्रिक नीतियों, अवस्फीति की धीमी गति, भू-राजनीतिक जोखिम और टैरिफ नीतियों की भावी दिशा संबंधी अनिश्चितता के चलते बीच-बीच में आई अस्थिरता के बावजूद, वृद्धि हुई।

1.8 ब्राजील ने वर्ष 2023-24 के लिए दिसंबर 2023 से भारत से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की और वर्ष के अंत में इसे दक्षिण अफ्रीका को सौंप दिया, जिससे ग्लोबल साउथ के तीन देशों का एक ऐतिहासिक त्रिकुट बन गया। 'बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट' इस व्यापक विषय के तहत, ब्राजील अध्यक्षता में तीन प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई: (क) भूख, गरीबी और असमानता का मुकाबला करना; (ख) टिकाऊ विकास के तीन आयामों को आगे बढ़ाना - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण; और (ग) वैश्विक अभिशासन संरचनाओं में सुधार करना। ब्राजील अध्यक्षता ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, सीमा पार भुगतानों का एकीकरण करने, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) की कमजोरियों को संबोधित करने, जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने जैसी पहल की।

घरेलू अर्थव्यवस्था

1.9 कई विपरीत परिस्थितियों के बीच, स्थिर वैश्विक संवृद्धि की पृष्ठभूमि में, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचों, सक्रिय नीतिगत उपायों और निरंतर सरकारी पूंजीगत व्यय के बल पर 2024-25 के दौरान सुदृढ़

रही। यद्यपि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)³ वृद्धि वर्ष 2024-25 में घटकर 6.5 प्रतिशत हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही। आर्थिक क्रियाकलापों को, व्यय पक्ष पर उपभोग मांग और निवल निर्यातों में सुधार तथा आपूर्ति पक्ष में सक्रिय सेवा क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन में सुधार, से सहायता मिली।

1.10 वर्ष 2024-25 में पर्याप्त जलाशय स्तरों और अनुकूल मौसम की स्थितियों के कारण कृषि और संबद्ध क्षेत्र में योजित सकल मूल्य (जीवीए) में वृद्धि 4.6 प्रतिशत रही, जो सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा के चलते खाद्यान्न के उल्लेखनीय उत्पादन द्वारा संचालित थी, जबकि एक वर्ष पहले यह वृद्धि 2.7 प्रतिशत थी। प्याज और आलू के अधिक उत्पादन से बागवानी क्षेत्र ने भी पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। सरकार ने अभिनव किसान-केंद्रित डिजिटल सेवाएं लाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन भी शुरू किया है, जो किसानों को पारदर्शी, कुशलक्षम, सुलभ और द्रुत सेवा वितरण सुविधा उपलब्ध कराएगा। इससे भारत के कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता भी बढ़ेगी। इसके अलावा, सरकार कृषि क्षेत्र में जलवायु-समुत्थानशीलता बढ़ाने और फसल की उपज में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन और उसके वितरण को बढ़ावा दे रही है।

1.11 वर्ष 2024-25 में, मुख्य रूप से विनिर्माण जीवीए में मंदी के कारण, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई। विनिर्माण क्षेत्र में 2024-25 की पहली तिमाही में मजबूत वृद्धि देखी गई, लेकिन अगली तीन तिमाहियों में इस वृद्धि में कमी आई, जो आधार प्रभाव और मांग की कमी, दोनों को परिलक्षित करती है। वर्ष के दौरान विस्तारित मानसून के चलते खनन क्षेत्र

³ जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, इस रिपोर्ट में जीडीपी डेटा के सभी संदर्भ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 28 फरवरी 2025 को जारी 'राष्ट्रीय आय 2024-25' के दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) पर आधारित हैं।

में मंदी बनी रही, जिससे 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान खनन गतिविधि प्रभावित हुई। औसत से अधिक मानसून और अपेक्षाकृत हल्की सर्दी के कारण बिजली की मांग में कमी आई जिससे बिजली उत्पादन में मामूली वृद्धि दर्ज हुई। निवेश वृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र 2024-25 में भी प्रमुख रहा। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने कई प्रमुख विनिर्माण उद्योगों में विकास की रफ्तार बनाए रखने में मदद की। नवंबर 2024 तक इस योजना के अंतर्गत पीएलआई योजना के तहत निवेश समग्र प्रतिबद्ध लक्ष्य के 57 प्रतिशत तक पहुंच गया।

1.12 वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र, जिसकी जीवीए में 64.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही, 7.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल आपूर्ति का मुख्य आधार बना रहा। निर्माण गतिविधि नरमी के बावजूद सुदृढ़ बनी रही और इसकी हिस्सेदारी 2012-13 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। केंद्र और राज्य सरकारों के मजबूत व्यय के साथ-साथ अन्य सेवाओं में कारोबार की गति स्थिर बने रहने के कारण लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) में तेजी रही, और उसमें पिछले आठ वर्षों में अपनी उच्चतम वृद्धि दर्ज की। इस बीच, व्यापार गतिविधि संवृद्धि में; और दूरसंचार ग्राहक आधार में वर्ष के दौरान में कमी आई।

1.13 वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) डेटा के अनुसार श्रम बाजार जनवरी- दिसंबर 2024 के दौरान समुत्थानशील रहा। महामारी के बाद कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में आई वृद्धि वर्ष 2024 में उलट गई, जबकि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में अन्य सेवाओं, निर्माण और व्यापार क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ी। शहरी क्षेत्रों से संबंधित अक्टूबर-दिसंबर 2024 के दौरान का त्रैमासिक पीएलएफएस डेटा भी मजबूत रोजगार की स्थिति का संकेत देता है।

1.14 जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध विश्व स्तर पर समन्वित कार्रवाई संबंधी अनिश्चितता के बावजूद, भारत अपने शमन और अनुकूलन प्रयासों पर केंद्रित रहा। यह जलवायु परिवर्तन

प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) 2025 में भी परिलक्षित होता है, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 से लगातार छठे वर्ष शीर्ष 10 उच्च प्रदर्शन करने वालों में स्थान प्राप्त किया है। 2024-25 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे अधिक वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा प्रमुख रही। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 10 लाख से अधिक परिवारों ने छत पर सोलर पैनल लगवाए। वर्ष के दौरान नॅशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में प्रगति के अलावा ग्रीन स्टील मिशन और क्रिटिकल मिनरल्स मिशन शुरू किए गए। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (ई-ड्राइव) योजना के माध्यम से परिवहन प्रणाली को स्वच्छ बनाने के प्रयासों को मजबूत किया गया, जिसमें हरित परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण पारितंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि 2030 तक 30 प्रतिशत ईवी अपनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था को हरित बनाने के उद्देश्य से किए गए उपाय, जैसे कि सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी करना, ग्रीन डिपॉजिट योजना और संशोधित पीएसएल दिशानिर्देश के माध्यम से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए समर्थन बढ़ाना, टिकाऊ विकास के लिए संसाधनों को सुविधाजनक बनाने के प्रति ठोस प्रतिबद्धता का प्रमाण देते हैं।

1.15 वर्ष 2024-25 के दौरान निविष्टि लागत के दबाव में आई कमी, सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपाय और पिछले मौद्रिक नीति कार्यों के निरंतर प्रसारण से मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब पहुंच गई। मुख्य रूप से कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) में 3.5 प्रतिशत की गिरावट और ईंधन में 2.5 प्रतिशत की अपस्फीति के चलते हेडलाइन मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 5.4 प्रतिशत से घटकर 2024-25 के दौरान औसतन 4.6 प्रतिशत हो गई। कोर मुद्रास्फीति में गिरावट सभी वस्तुओं और सेवाओं में व्यापक आधार पर थी। वर्ष की दूसरी छमाही में कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हुई वृद्धि से प्रेरित थी।

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल शुल्क में बढ़ोतरी से भी सेवा मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में नरमी आने के कारण लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और केरोसिन की कीमतें कम हुईं जिससे ईंधन मुद्रास्फीति में गिरावट आई। इसके विपरीत, मौसम के अनपेक्षित बदलाव से उत्पन्न कई आपूर्ति आघातों के कारण 2024-25 में खाद्य मुद्रास्फीति में बीच-बीच में तीव्र वृद्धि हुई और वह 6.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही, जिससे हेडलाइन मुद्रास्फीति अस्थिर रही। खाद्य मुद्रास्फीति ने वर्ष के दौरान अक्टूबर 2024 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो मार्च 2025 तक अनपेक्षित रूप से घटकर 2.9 प्रतिशत हो गई। एक ओर जहां सब्जी मुद्रास्फीति ने वर्ष के दौरान अत्यधिक अस्थिरता का अनुभव किया, वहीं अनाज, फल, खाद्य तेल और मांस तथा मछली संबंधी मुद्रास्फीति तटस्थ बनी रही, जो आपूर्ति में कमी की स्थिति को दर्शाती है। घरेलू आयात शुल्क में वृद्धि और इंडोनेशिया द्वारा खाद्य तेलों पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों ने खाद्य मुद्रास्फीति को सख्त बना दिया।

1.16 संवृद्धि-मुद्रास्फीति के परस्पर संबंध को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अक्टूबर 2024 में नीतिगत समायोजन रुख बदलकर तटस्थ की ओर किया, जिससे अवस्फीति और संवृद्धि पर दृष्टिकोण और प्रगति की निगरानी करने और बदलती स्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए लचीलापन प्राप्त हुआ। इसके बाद, संवृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता ने संवृद्धि का समर्थन करने के लिए नीतिगत अवसर उपलब्ध कराया जिसके साथ एमपीसी ने फरवरी 2023 से 6.50 प्रतिशत पर जो स्थिति बनाए रखी थी उसे फरवरी 2025 में नीति रेपो दर को 25 बीपीएस घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया। गत वर्ष की तुलना में 2024-25 के दौरान चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन, वर्ष के दौरान ही, प्रणालीगत चलनिधि, जो जुलाई-नवंबर 2024 के दौरान अधिशेष में थी, दिसंबर 2024-मार्च 2025 के दौरान कमी में चली गई। ऐसा संचलन में मुद्रा की उच्च वृद्धि और रिजर्व बैंक

के विदेशी मुद्रा संचालन के कारण हुआ। समग्र रूप से देखें तो वर्ष के दौरान चलनिधि की स्थिति अधिशेष में बनी रही, जो चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण में परिलक्षित होता है, जो पिछले वर्ष के 485 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 के दौरान 1,605 करोड़ रुपये हो गई। रिजर्व बैंक ने प्रणाली को टिकाऊ चलनिधि प्रदान करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 50 बीपीएस (25 बीपीएस के दो किस्त) तक कम करने के अलावा, खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीद, अमरीकी डॉलर/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप और लंबी अवधि के परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) परिचालन सहित बाजार परिचालनों का एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया। भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) ने, 2024-25 के दौरान नीति रेपो दर से औसतन 6 बीपीएस ऊपर कारोबार किया।

1.17 घरेलू वित्तीय बाजार 2024-25 के दौरान, अनिश्चित वैश्विक वातावरण के बीच, समुत्थानशील रहे। सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) और कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में वर्ष के दौरान गिरावट आई, जिससे कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गम में वृद्धि हुई। घरेलू शेयरों ने पहली छमाही में नई ऊंचाइयां दर्ज कीं लेकिन जीडीपी वृद्धि और कंपनियों की आय में नरमी, टैरिफ नीति में अनिश्चितता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के सतत बाह्य प्रवाह से जुड़ी चिंताओं के बीच दूसरी छमाही में उसमें गिरावट आई। प्राथमिक बाजार गतिविधि में चौथी तिमाही में नरमी रहने के बावजूद वह 2024-25 में बेहतर बनी रही।

1.18 अमेरीकी डॉलर और यूएस आस्ति प्रतिफल मजबूत बने रहने के कारण भारतीय रुपए (आईएनआर) में कुछ गिरावट आई, लेकिन अपने कुछ ईएमई साथी देशों की तुलना में वह कम थी। इसके बावजूद, भारत के मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचों ने, चालू खाता और राजकोषीय घाटा स्थिर और नरम रहने पर भी, आईएनआर के समयानुकूल विकास को संभव बनाया। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय सीमा

पार लेनदेन के लिए भागीदार व्यापारिक देशों की आईएनआर और स्थानीय मुद्राओं के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए और विदेशी मुद्रा लेनदेन करने में आसानी के लिए विनियामक, पर्यवेक्षी और प्राधिकृतिकरण ढांचे को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

1.19 वर्ष 2024-25 के दौरान बैंकों की जमा और उधार दरों में नीतिगत रेपो दर में बदलाव का प्रसारण सुदृढ़ रहा। कुल बकाया अस्थायी दर ऋणों में बाह्य बेंचमार्क आधारित ऋण का अनुपात वर्ष के दौरान और बढ़ गया, और निधि की सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) से संबद्ध ऋणों में समान रूप से गिरावट आई।

1.20 केंद्र सरकार ने अपनी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रतिबद्धता को पूरा किया, जिसके परिणामस्वरूप सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) कम होकर 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.7 प्रतिशत तक हो गया [संशोधित अनुमान (आरई)] जो 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत⁴ था। व्यय पक्ष को देखें तो प्रभावी पूंजीगत व्यय ने⁵ 2023-24 में दर्ज 19.8 प्रतिशत से अधिक 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि राजस्व व्यय में वृद्धि 2024-25 (आरई) में 5.8 प्रतिशत थी। प्राप्ति पक्ष पर, सकल-कर और गैर-कर प्राप्तियों ने 2024-25 (संशोधित अनुमान) में क्रमशः 11.2 प्रतिशत और 32.2 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की। अप्रैल 2024 - फरवरी 2025 के दौरान अनंतिम खातों के आंकड़ों से पता चलता है कि कर राजस्व वृद्धि में गिरावट और केंद्र सरकार से अनुदानों में गिरावट के कारण राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में मध्यम वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल 2024 - फरवरी 2025 के दौरान राज्यों के राजस्व व्यय में वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं हुआ। फिर भी,

राज्यों का समेकित जीएफडी 2024-25 में जीडीपी के 3.2 प्रतिशत के बजट अनुमान के भीतर रहने की संभावना है।

1.21 रिज़र्व बैंक ने राज्य वित्त सचिवों (एसएफएस) के 33वें सम्मेलन के तत्वावधान में गठित कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमाओं को संशोधित किया। राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों की डब्ल्यूएमए सीमा को बढ़ाकर ₹60,118 करोड़ कर दिया गया जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। पहले यह सीमा ₹47,010 करोड़ थी। समेकित सिंकिंग फंड (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) पर रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) सीमाओं को संशोधित किया गया ताकि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके नकदी प्रवाह में, उनकी अस्थायी विसंगति को प्रबंधित करने के लिए, अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके।

1.22 भारत के पण्य निर्यात में 2024-25 में 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले इसमें 3.1 प्रतिशत का संकुचन हुआ था। वहीं दूसरी ओर वस्तुओं के आयात में इस अवधि में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में इसमें 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी। परिणामस्वरूप, भारत का पण्य व्यापार घाटा 2024-25 के दौरान बढ़कर 282.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 241.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। बहरहाल, मजबूत सेवा निर्यात और आवक विप्रेषण में स्थिर प्रवाह से भारत के सीएडी को अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 1.3 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 1.1 प्रतिशत) के स्वीकार्य स्तर के भीतर बने रहने के लिए मदद मिली।

1.23 पूंजी प्रवाहों में वर्ष के दौरान उतार-चढ़ाव रहा। निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 2024-25 के दौरान

⁴ आंकड़े केंद्रीय बजट 2025-26 में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि उनकी गणना सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम उपलब्ध अनुमानों का उपयोग करके की गई है।

⁵ पूंजीगत आस्तित्व सृजन के लिए पूंजीगत व्यय और सहायता अनुदान का जोड़।

0.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो एक वर्ष पहले के 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था। एफपीआई ने 2024-25 के दौरान 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष पहले 41.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवल प्रवाह दर्ज किया। बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं के संदर्भ में निवल पूंजी प्रवाह 2024-25 की पहली छमाही में सीएडी के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त से अधिक था, और तदनुसार, 23.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार (बीओपी आधार पर) में अभिवृद्धि हुई। तथापि दूसरी छमाही में स्थिति उलट गई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के दौरान 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल बहिर्वाह के साथ घरेलू बाजार में निवल ब्रिकी की। उल्लेखनीय है कि, ऋण खंड में निवल एफपीआई प्रवाह ने 2024-25 के दौरान 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रवाह के साथ सुदृढ़ता प्रदर्शित की। पूंजी प्रवाह के अन्य रूप, जैसे कि बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और अनिवासी जमाराशियां मजबूत रहीं, 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान निवल पूंजी प्रवाह सीएडी से कम हो गया, जिससे रिजर्व में (बीओपी आधार पर) 37.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी हो गई। कुल मिलाकर, अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान रिजर्व में 13.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई। फिर भी, 11 महीने के पण्य आयात के भुगतान के लिए 668.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (मार्च अंत तक) के पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में मजबूत बफर ने बाहरी वित्तपोषण आवश्यकताओं और प्रतिकूल वैश्विक प्रसार-प्रभाव को कम करने में मदद की।

1.24 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण-जमा अनुपात में वर्ष के दौरान मामूली वृद्धि हुई, क्योंकि बैंक ऋण-वृद्धि तुलनात्मक रूप से जमा-वृद्धि से अधिक रही। तथापि, ऋण और जमा वृद्धि के बीच का अंतर कम हो गया क्योंकि बैंकों ने वित्तपोषण अंतर को पाटने के लिए जमाराशियां जुटाने हेतु अपनी सावधि जमा दरों में वृद्धि जारी रखी। एससीबी

की आस्ति गुणवत्ता में और भी सुधार हुआ, जो सकल एनपीए (जीएनपीए) अनुपात और निवल एनपीए (एनएनपीए) अनुपात दोनों में कमी दिखाई देने और स्लिपेज अनुपात में लगातार गिरावट से स्पष्ट होता है। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) के साथ-साथ लाभप्रदता संकेतक, अर्थात, आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) मजबूत रहे, जबकि निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) कम हुआ। पूंजी और चलनिधि बफर विनियामक आवश्यकताओं से काफी ऊपर रहे। मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट से पता चलता है कि सभी प्रतिकूल परिदृश्यों में बैंकों की कुल पूंजी न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से अधिक रहेगी।

1.25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा दिए जाने वाले सकल ऋण में दिसंबर 2024 के अंत तक दोहरे अंकों में वृद्धि हुई, जबकि जोखिम भार में वृद्धि किए जाने के कारण सुरक्षा-रहित ऋण वितरण में कुछ गिरावट रही। इस अवधि के दौरान लाभप्रदता संकेतकों और एनपीए अनुपात में और सुधार जारी रहा, और पूंजी पर्याप्तता अनुपात मजबूत रहा। एनबीएफसी को दिए जाने वाले बैंक ऋण पर जोखिम भार कम करके उसे 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी कर दिया गया ताकि ऋण लेना सुगम हो सके और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।

1.26 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की ऋण वृद्धि में दिसंबर 2024 के अंत तक सुधार हुआ। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मजबूत पूंजी बफर और जीएनपीए अनुपात घटने के कारण यूसीबी के वित्तीय निष्पादन में भी सुधार हुआ।

1.27 अभिशासन, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और परिचालन समुत्थानशीलता को मजबूत करने की दिशा में वर्ष के दौरान वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप कई विनियामक और पर्यवेक्षी दिशानिर्देश जारी किए गए जो अन्य बातों के साथ-साथ: (क) ऋण संबंधी मॉडल जोखिमों के प्रबंधन सिद्धांतों; (ख) लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के यूनिवर्सल बैंकों के रूप में

स्वैच्छिक अंतरण के लिए पात्रता मानदंड; (ग) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और एनबीएफसी पर लागू विनियमों के सुसंगतीकरण; और (घ) परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन समुत्थानशीलता बढ़ाने से संबंधित हैं।

1.28 पर्यवेक्षण क्षेत्र में, रिजर्व बैंक सक्रिय रूप से पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के साथ जुड़ा रहा ताकि अभिशासन और आश्वासन कार्यों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन से संबंधित अपेक्षाओं को अवगत कराया जा सके। पर्यवेक्षी पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं (क) पर्यवेक्षी प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी तकनीकों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उन्नत पर्यवेक्षी विश्लेषण समूह की स्थापना; (ख) वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख वैश्विक अधिकार क्षेत्रों के प्राधिकारियों के साथ औपचारिक संबंधों को स्थापित और गहरा करके अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षी सहयोग को सक्रिय रूप से मजबूत करना; (ग) एसई में जोखिम आंकड़ा एकत्रीकरण क्षमताओं और जोखिम रिपोर्टिंग पद्धतियों में कमियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए पर्यवेक्षी आंकड़ा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्यूआई) का विकास; (घ) यूसीबी के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के संबंध में दिशानिर्देश जारी करना; और (ङ) सभी एसई के ऑनसाइट / ऑफसाइट आकलन के माध्यम से साइबर जोखिम निरीक्षण को मजबूत करना।

1.29 केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)-रिटेल (e₹-R) के संबंध में व्यक्ति-से-व्यक्ति (पीटूपी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पीटूएम) के प्रारंभिक उपयोग के मामलों से शुरू करके रिजर्व बैंक ने 2024-25 के दौरान उसे, ऑफलाइन और प्रोग्रामेबिलिटी सुविधाओं को शामिल करने के लिए पायलट प्रयास बढ़ाए। मार्च 2025 के अंत तक, e₹-खुदरा खंड में पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार 17 बैंकों तक किया गया था और दिसंबर 2022 में इसकी स्थापना के बाद से 60 लाख उपयोगकर्ता शामिल किए गए। इसे अधिक पैमाने पर अपनाए जाने और इसके वितरण में सुधार करने के लिए कुछ गैर-बैंक संस्थाओं को सीबीडीसी वॉलेट की पेशकश करने की अनुमति

दी गई है। इसके अलावा e₹-थोक के दायरे को बढ़ाया गया और चार एकल प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को शामिल करने के साथ-साथ उसमें विविधता लाई गई।

1.30 भारत रणनीतिक रूप से एआई के लिए एक मजबूत पारितंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि इस उभरते क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। सरकार ने *इंडियाएआई मिशन* और तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) - स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरों में एआई की स्थापना जैसे, कई प्रयास शुरू किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में एआई नवाचार का समर्थन करने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत तेजी से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहल के माध्यम से एक मजबूत सेमीकंडक्टर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है।

1.31 वित्तीय पारितंत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग और उसे अपनाए जाने पर निगरानी पर रिजर्व बैंक का ध्यान है जिसके लिए 28 मई 2024 को 'फिनटेक रिपोजिटरी' की एक अनूठी पहल शुरू की गई। इस रिपोजिटरी का उद्देश्य फिनटेक संस्थाओं और उनकी प्रौद्योगिकी स्थिति के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना है। इसके अलावा, विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे कि, एआई, एमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) आदि को अपनाए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 'एमटेक रिपोजिटरी' भी शुरू की गई। ये सुरक्षित वेब आधारित एप्लीकेशन हैं और इनका प्रबंधन रिजर्व बैंक इन्नोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा किया जाता है। ये रिपोजिटरियां समग्र क्षेत्रीय स्तर का डेटा, रुझान और विश्लेषण उपलब्धता करांगी, जो नीति निर्माताओं और सहभागी उद्योग सदस्यों, दोनों के लिए उपयोगी होंगे।

1.32 वर्ष 2024-25 के दौरान कुल डिजिटल भुगतान ने मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 34.8 प्रतिशत और 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की सफलता ने भारत को वैश्विक वास्तविक समय भुगतान में 48.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी के

साथ शीर्ष स्थान पर रखा है⁶। रिजर्व बैंक ने 'भुगतान विज्ञान 2025' दस्तावेज में निर्धारित कार्यक्रम पत्र के अनुसार कार्य करना जारी रखा। 'समावेशन स्तंभ' के तहत, डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग को गहन करने के लिए 'प्रत्यायोजित भुगतान' (डेलिगेटेड पेमेंट्स) शुरू किया गया। यह सुविधा व्यक्तियों (प्राथमिक उपयोगकर्ता) को किसी अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) द्वारा प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते से एक सीमा तक यूपीआई लेनदेन करने की अनुमति देती है। इसके अलावा, भुगतान प्रणाली की पहुंच को बढ़ावा देने और समावेशी विकास बढ़ाने के लिए सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों को सूचित किया गया कि वे अपनी भुगतान प्रणालियों/उपकरणों की समीक्षा करें और दिव्यांग जनों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए आवश्यक संशोधन करें।

1.33 विनियामक प्रयासों ने साइबर सुदृढ़ता पर जोर देने के साथ धोखाधड़ी रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करने और सूचना सुरक्षा तैयारियों को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) रिपोर्टिंग में वर्ष के दौरान बैंकों की विभिन्न श्रेणियों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए साइबर सुरक्षा जोखिमों और कमजोरियों की पहचान, विश्लेषण, निगरानी और प्रबंधन के लिए मजबूत अभिशासन तंत्र भी निर्धारित किए गए।

1.34 डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए, रिजर्व बैंक ने 7 फरवरी 2025 को 'bank.in' के रूप में भारत में बैंकों के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन शुरू करने का प्रस्ताव रखा। यह पहल डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में विश्वास बढ़ाने और सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने में सहायता करेगी। विशेष इंटरनेट

डोमेन साइबर सुरक्षा खतरों और फिशिंग जैसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की पहचान करने में भी मदद करेंगे और आम जनता को होने वाले वित्तीय नुकसान की घटनाओं को कम करेंगे। इसी पहल के रूप में भारतीय वित्तीय क्षेत्र में अन्य गैर-बैंक संस्थाओं के लिए 'fin.in' के रूप में एक विशिष्ट डोमेन रखने का भी प्रस्ताव है।

1.35 सीमा-पार भुगतान क्षेत्र में, रिजर्व बैंक तत्काल सीमा-पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल 'प्रोजेक्ट नेक्सस' में शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) और भारत की तीव्र भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) को जोड़ना है।

1.36 रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स)⁷, जो देश में वित्तीय समावेशन की व्याप्ति को मापता है, मार्च 2023 में 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया, जिसमें पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के सभी तीन उप-सूचकांकों में वृद्धि देखी गई। एफआई सूचकांक में सुधार मुख्य रूप से 'उपयोग' उप-सूचकांक का योगदान रहा, जो वित्तीय समावेशन की गहरी पहुंच को परिलक्षित करता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) 2025 भी 24-28 फरवरी 2025 के दौरान 'वित्तीय साक्षरता - महिलाओं की समृद्धि' विषय पर मनाया गया, जिसमें महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

1.37 उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सुचारु दृष्टिकोण अपनाया। रिजर्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना के तहत अपनाई गई प्रक्रियाओं को, दक्षता बढ़ाने के लिए, और अधिक परिष्कृत किया गया।

⁶ एसीआई वर्ल्डवाइड, 2024।

⁷ 'मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक' पर रिजर्व बैंक की 9 जुलाई 2024 को जारी प्रेस प्रकाशनी।

1.38 रिज़र्व बैंक ने 2024-25 के दौरान अपनी स्थापना के 90वें वर्ष को वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ मनाया जो रिज़र्व बैंक की नौ दशकों (आरबीआई@90) की विरासत को दर्शाते हैं, और आने वाले दशक (आरबीआई@100) के लिए रणनीतियों की दिशा दिखाते हैं। इस स्मरणोत्सव का शुभारंभ 1 अप्रैल 2024 को उद्घाटन समारोह के साथ किया गया, जिसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री मुंबई में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। स्मरणोत्सव का समापन 1 अप्रैल 2025 को मुंबई में भारत के महामहिम राष्ट्रपति की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम के साथ हुआ।

3. 2025-26 के लिए संभावनाएं

वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.39 वर्ष 2025 और 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण कई चुनौतियों से घिरा हुआ है, जैसे कि - अवस्फीति की गति कम होना; कई अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक सार्वजनिक ऋण; भू-राजनीतिक तनाव बना रहना; बढ़ा हुआ व्यापार तनाव; वित्तीय बाजार में अस्थिरता; और जलवायु आघात। वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2025 में 2.8 प्रतिशत और 2026 में 3.0 प्रतिशत (2024 में 3.3 प्रतिशत) बढ़ने का अनुमान⁸ है। ईएमडीई में संवृद्धि 2025 में 3.7 प्रतिशत अनुमानित है और 2026 में मामूली सुधार के साथ उसके 3.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है। ईई में संवृद्धि दर 2024 के 1.8 प्रतिशत से घटकर 2025 में 1.4 प्रतिशत और 2026 में उसमें मामूली सुधार हो कर वह 1.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

1.40 वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 के 5.7 प्रतिशत से घटकर 2025 में 4.3 प्रतिशत और 2026 में 3.6 प्रतिशत होने की उम्मीद है। लेकिन, निकट अवधि में मूल्य स्थिरता के दिशापथ को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि

दुनिया के कई हिस्सों में सेवा मुद्रास्फीति जड़ बनी हुई है, बढ़ाए गए टैरिफ यूएस में मुद्रास्फीति बढ़ा रहे हैं और मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं में भिन्नता होने के संभावित जोखिम हैं।

1.41 14 अप्रैल 2025 की टैरिफ स्थिति के आधार पर समायोजित परिदृश्य के तहत वैश्विक पण्य व्यापार की मात्रा 2025 में 0.2 प्रतिशत से संकुचित होने का अनुमान है⁹। हालाँकि, 8 मई 2025 को यूएस और यूके के बीच एक व्यापार समझौते पर हुए हस्ताक्षर और 12 मई 2025 को अमेरिका और चीन द्वारा जवाबी कदम को समाप्त करने और भविष्य की चर्चाओं में शामिल होने के लिए किया गया समझौता वैश्विक व्यापार के लिए अच्छा संकेत है।

1.42 प्रमुख आई और ईएमई में सार्वजनिक ऋण के उच्च स्तर इन अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक वित्त की स्थिरता के बारे में चिंता पैदा करते हैं और वे वित्तीय बाजार की पहले से ही बढ़ी हुई अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। प्रणालीगत अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ा हुआ सॉवरेन ऋण स्तर पहले से ही जोखिम प्रीमियम और प्रतिफल में प्रतिकूलता का कारण बन रहा है। आस्तित्व मूल्यांकनों में वृद्धि और प्रतिफलों की प्राप्ति के लिए पूंजी प्रवाह होने से वित्तीय स्थितियां कठिन बन सकती हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं, जैसा कि 2024 के दौरान वैश्विक इक्विटी बाजारों में बिक्री दबावों की घटनाओं से स्पष्ट होता है। प्रणालीगत आई के वित्तीय बाजारों में अव्यवस्थित समायोजन का प्रतिकूल असर, अब तक बने हुए भू-राजनीतिक तनाव, भू-आर्थिक विखंडन, व्यापार तनाव के उद्भव और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी आघातों के बीच, ईएमडीई पर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टो मुद्रा, फिनटेक, सीबीडीसी और एआई/एमएल के माध्यम से होने वाले तकनीकी व्यवधानों के लिए भी वैश्विक स्तर पर समन्वित नीति प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

⁸ वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2025, आईएमएफ।

⁹ ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक अपडेट, अप्रैल 2025, डब्ल्यूटीओ।

घरेलू अर्थव्यवस्था

1.43 वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण आशाजनक बना हुआ है, जिसे उपभोग मांग में वापसी, सरकार का राजकोषीय सुदृढीकरण को जारी रखते हुए, पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर, बैंकों और कॉरपोरेट्स के स्वस्थ तुलनपत्र, वित्तीय स्थितियों में सुगमता, सेवा क्षेत्र में बनी रही समुत्थानशीलता और मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचों के अलावा उपभोक्ता और व्यावसायिक आशावाद को मजबूत होने से मदद मिली है। तथापि, संरक्षणवादी मार्ग अपनाए जाने के कारण वैश्विक व्यापार के बारे में अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव के बने रहने और वैश्विक वित्तीय बाजार में आई अस्थिरता विकास परिदृश्य के लिए अधोमुखी जोखिम और मुद्रास्फीति परिदृश्य के लिए उर्ध्वमुखी जोखिम पैदा करती हैं।

1.44 दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद और उत्पादकता-बढ़ाने वाली विभिन्न सरकारी नीतियों के कारण 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाएं अनुकूल दिखाई देती हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की गई है, जैसे - प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना¹⁰; दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन; सब्जियों और फलों के उत्पादन, कुशल आपूर्ति और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करना; उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन¹¹ की शुरुआत; कपास उत्पादकता मिशन; और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण सीमा को 3

लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना। इसके अलावा, जैविक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए टिकाऊ कृषिकार्य को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्र के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए 'प्राकृतिक कृषिकार्य के लिए राष्ट्रीय मिशन' के तहत एक करोड़ किसानों को शामिल करने की योजना शामिल है।

1.45 वर्ष 2025-26 में विनिर्माण क्षेत्र को घरेलू मांग में सुधार, उच्च क्षमता उपयोग, कॉरपोरेट्स और बैंकों के स्वस्थ तुलनपत्र और उपभोक्ता तथा व्यावसायिक आशावाद के कारण अधिक तेजी प्राप्त होने की उम्मीद है। वर्तमान में चल रही पीएलआई योजना और केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित 'राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन'¹² के माध्यम से विनिर्माण आधार और नीतिगत समर्थन को व्यापक बनाने पर सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' पहल को और मजबूत बनाए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए आवंटन में वृद्धि के कारण 2025-26 में निर्माण क्षेत्र में भी मजबूत प्रदर्शन बने रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, दूसरी चरण की आस्ति मुद्रीकरण योजना (2025-30) की घोषणा, जिसका उद्देश्य आस्ति मुद्रीकरण के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये जुटाना है, जिससे बुनियादी ढांचा क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इन कारकों से रोजगार के नए अवसर पैदा होने, श्रम आय में सुधार और घरेलू मांग में मजबूती आने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए भविष्योन्मुखी सर्वेक्षणों में भी विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बारे में आशावाद परिलक्षित होता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए

¹⁰ इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, मध्यम फसल प्राप्ति और औसत से कम ऋण पैरामीटरों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसका प्रयोजन होगा: (ए) कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाना; (बी) फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाया जाना; (सी) पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरान्त भंडारण में वृद्धि करना; (डी) सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाना; और (ई) दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना।

¹¹ इसका उद्देश्य: (क) अनुसंधान पारितंत्र को मजबूत करना; (ख) उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोध और जलवायु अनुकूल वाले बीजों का लक्षित विकास और प्रचार; और (सी) जुलाई 2024 से जारी 100 से अधिक बीज किस्मों की वाणिज्यिक उपलब्धता।

¹² पांच मुख्य क्षेत्रों पर जोर: (क) व्यापार करने में आसानी और लागत; (बी) भविष्य के लिए तैयार कार्यबल; (ग) सक्रिय और गतिशील सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र; (घ) प्रौद्योगिकी की उपलब्धता; और (ई) गुणवत्तायुक्त उत्पाद।

वास्तविक जीडीपी संवृद्धि, समान रूप से संतुलित जोखिमों के साथ, 6.5 प्रतिशत अनुमानित है।

1.46 देश के ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता के लिए 100 गीगावाट (गी.वा) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) पर, उनके छोटे आकार और कम पूंजी निवेश आवश्यकता के कारण, जोर देने से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट में बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए राज्यों को वितरण और पारेषण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के वित्त पोषण के लिए बड़ी वृद्धि की गई है, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना है।

1.47 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए बजट प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में 2025-26 में दोगुने से अधिक है। यह सकल घरेलू उत्पाद में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्यय के भारत के अपेक्षाकृत कम हिस्से (0.6 प्रतिशत) को बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम है ताकि चीन (2.4 प्रतिशत), कोरिया (4.8 प्रतिशत) और मलेशिया (1 प्रतिशत)¹³ जैसे देशों के स्तरों तक पहुंचा जा सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए बढ़ाए गए बजट से भारत के नवाचार परिदृश्य और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जो दीर्घावधि में उत्पादकता वृद्धि के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अपनी एआई क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए¹⁴ सरकार ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) और समस्या-विशिष्ट एआई समाधानों सहित कई राष्ट्रीय आधारभूत एआई

मॉडलों के विकास के लिए सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है।

1.48 वर्ष 2024-25 में, सरकार के आपूर्ति प्रबंधन उपायों ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखा और प्रणाली में संचालित मौद्रिक नीति सख्ती के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति 73 बीपीएस से घटकर 4.6 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, आपूर्ति शृंखला दबाव के घटने, वैश्विक पण्य कीमतों में नरमी, सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून द्वारा समर्थित उच्च कृषि उत्पादन की उम्मीद और उच्च जलाशय स्तर 2025-26 में मुद्रास्फीति संभावना के लिए अच्छा संकेत देते हैं। तथापि, जलवायु संबंधी आघातों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए खाद्य मूल्य परिदृश्य की सावधानीपूर्वक निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। लंबे समय तक जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, वैश्विक वित्तीय बाजार में अत्यधिक अस्थिरता, व्यापार विखंडन और प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियां मुद्रास्फीति के बढ़ने का जोखिम पैदा करती हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.0 प्रतिशत अनुमानित है, जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

1.49 फरवरी और मार्च 2025 में मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे रही, तथा खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट रही जिसके कारण अधिक विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आगामी 12 महीनों में हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.0 प्रतिशत के लक्ष्य के पास स्थिर रूप से रह सकती है। मुद्रास्फीति के संभाव्य रूप से सौम्य रहने और अपेक्षाकृत रूप से संवृद्धि की धीमी गति को देखते हुए मौद्रिक नीति द्वारा संवृद्धि को समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही तेजी से बदलती वैश्विक समष्टि आर्थिक स्थितियों के बारे में सतर्क रहना भी जरूरी है। तदनुसार, एमपीसी ने अप्रैल 2025 की अपनी बैठक में सर्वसम्मति से नीति रेपो दर को 25 बीपीएस घटाकर 6.0 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया। इसके अलावा, एमपीसी

¹³ वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, विश्व बैंक।

¹⁴ केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा में एआई के लिए ₹500 करोड़ के परिव्यय के साथ चौथे सीआई की घोषणा की।

ने रुख को तटस्थ से उदार में बदलने का भी निर्णय लिया। रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रणाली चलनिधि को पर्याप्त रखने के लिए मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन परिचालन करना जारी रखेगा। बैंक मुद्रा बाजार ब्याज दरों के व्यवस्थित संचलन को सुनिश्चित करते हुए चलनिधि में अल्पकालिक अस्थिरता तथा टिकाऊ चलनिधि के प्रबंधन के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करेगा।

1.50 वर्ष 2025-26 में, यूएस की टैरिफ नीतियों के प्रभाव और दूसरों द्वारा किए गए जवाबी उपायों पर बाजार बारीकी से नजर रखेंगे क्योंकि अनिश्चित नीतिगत वातावरण वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता पैदा करेगा। भारतीय इक्विटी बाजार का, 2024 की दूसरी छमाही में गिरावट (करेक्शन) के बाद, व्यापक रूप से स्थिर आर्थिक स्थिति और इक्विटी बाजार मूल्यांकनों में कमी के बाद, समुत्थानशील बने रहने की उम्मीद है, हालांकि भू-राजनीतिक अनिश्चितता से गिरावट आने का जोखिम बना रहेगा। द्वितीयक बाजार की संवेदनशीलता स्थिर होने पर प्राथमिक बाजार के माध्यम से संसाधन जुटाने में तेजी आने की उम्मीद है। तथापि निकट अवधि में, वैश्विक नीतिगत अनिश्चितता के चलते, बाजार में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। दुनिया भर में संरक्षणवाद की प्रवृत्ति पर जोर है। इसके बावजूद सीमा पार लेनदेन के लिए बढ़ी हुई पहुंच और स्वीकार्यता के माध्यम से आईएनआर (अर्थात, INR का अंतरराष्ट्रीयकरण) के उपयोग को बढ़ावा देने के उपाय, और व्यापार-भागीदार देशों के साथ सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग वर्ष के दौरान जारी रहने की उम्मीद है, जैसा कि नवंबर 2024 में मालदीव और मार्च 2025 में मॉरीशस के साथ हस्ताक्षरित स्थानीय मुद्रा निपटान के लिए हुए समझौता ज्ञापनों में परिलक्षित होता है।

1.51 प्रभावी पूंजीगत व्यय को 2024-25 (आरई) के 4.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025-26 में जीडीपी का 4.3 प्रतिशत

करते हुए संवृद्धि को समर्थन देने वाले पूंजीगत व्यय को केंद्र सरकार द्वारा बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा, राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता योजना को 1.5 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने जीएफडी को 2025-26 (बीई) में जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर लक्षित करके 2025-26 (बीई) में जीएफडी को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के अपने मध्यम अवधि के उद्देश्य का पालन किया, जो 2024-25 (आरई) के 4.7 प्रतिशत से नीचे है। 2026-27 के बाद से, केंद्र सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को एक दिशापथ पर बनाए रखना है जिसके अनुसार मार्च 2031 के अंत तक जीडीपी की तुलना में लोक ऋण के अनुपात में लगभग 50 प्रतिशत की कमी की जानी है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों के संबंध में राजकोषीय दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जिसमें उनका समेकित जीएफडी बजट सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है¹⁵। 2025-26 के दौरान केंद्र से राज्यों को सकल अंतरण में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है, जो मुख्य रूप से कर अंतरण, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के रूप में है, जो उच्च पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त राजकोषीय अवसर प्रदान करता है।

1.52 चल रहे भू-राजनीतिक संघर्षों, भू-आर्थिक विखंडन और नीतिगत अनिश्चितता से उत्पन्न अधोगामी जोखिमों के कारण वैश्विक व्यापार में मंदी आ सकने की संभावना से भारत के पण्य निर्यात में अनिश्चितता की स्थिति हो सकती है। तथापि, विभिन्न व्यापार भागीदारों के साथ चल रही व्यापार करार वार्ताओं से वैश्विक व्यापार में भारत की अधिक भागीदारी सुकर बन सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और कृषि सहित प्रमुख निर्यात क्षेत्रों के विस्तार के

¹⁵ डेटा उन 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है जिन्होंने 2025-26 के लिए अपने बजट प्रस्तुत किए।

अलावा ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार में नवाचारों से भारत की निर्यात वृद्धि को लाभ होगा¹⁶।

1.53 भारत के सेवा व्यापार संतुलन और आवक विप्रेषण प्राप्तियों की मजबूत संभावओं के चलते 2025-26 के दौरान सीएडी को पूरी तरह से धारणीय सीमा के भीतर बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय सॉवरेन बॉण्डों को शामिल करने, और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने, जैसा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया है, से विदेशी निवेश प्रवाह बेहतर बना रहेगा। इसके अलावा, निर्यात अनुकूल वातावरण और भारत की तुलनात्मक रूप से अनुकूल स्थिति, क्षेत्रीय व्यापार करार की क्षमता के उपयोग, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) में अधिक भारतीय भागीदारी, भारत के पण्य व्यापार और सेवा समूह को नई सीमाओं में प्रस्तुत करते हुए विविधता प्रदान करना और आईएनआर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाना, भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा और आगे चलकर भारत के बाहरी क्षेत्र की समुत्थानशीलता को और मजबूत करेगा।

1.54 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र समुत्थानशील रहा है, तथापि बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताएं सक्रिय रूप से जोखिम प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करती है। ब्याज दर जोखिम की गतिशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को व्यापार और बैंकिंग, दोनों प्रकार के बही जोखिमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से एनआईएम के कम होने के संदर्भ में।

1.55 एनबीएफसी द्वारा बैंकों से निधि प्राप्त करने में कुछ कमी आई है लेकिन अभी भी वे काफी हद तक बैंक निधि पर निर्भर हैं। यह आवश्यक है कि वे अलग-अलग स्रोतों से निधि प्राप्त करें। पैमाना-आधारित विनियामक ढांचे से अभिशासन और जोखिम प्रबंधन में और सुधार होने की उम्मीद है।

1.56 रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणाली को अधिक समुत्थानशील, सशक्त, सुरक्षित और समावेशी बनाने के लिए विनियमन, पर्यवेक्षण, फिनटेक, भुगतान प्रणाली, ग्राहक संरक्षण और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में कई पहल करेगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक सुरक्षित, सुलभ, किफायती और दक्ष वित्तीय क्षेत्र निर्माण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा।

1.57 कारोबार की दक्षता बढ़ाने और अनुपालन को सरल बनाने के लिए रिज़र्व बैंक विनियामकीय क्षेत्र में विनियमनों को एकीकृत और सुसंगत बनाएगा। PRAVAAH¹⁷ पोर्टल मई 2024 में शुरू किया गया था। 1 मई, 2025 से आरई के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे रिज़र्व बैंक को अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग करें। संशोधित अनुमान के लिए को रिज़र्व बैंक को अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए। बैंक इस पोर्टल की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना जारी रखेगा।

1.58 रिज़र्व बैंक जोखिमों और कमजोरियों की शीघ्र पहचान करने, कमजोरियों के मूल कारण पर ध्यान केंद्रित करने और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न खंडों में पर्यवेक्षी कठोरता को सुसंगत बनाने के उद्देश्य से पर्यवेक्षी पहलों को जारी रखेगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक वित्तीय संस्थाओं के लिए आधारभूत साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों में एकरूपता पर अंतर-विनियामक कार्य समूह की सिफारिशों को लागू करके पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की साइबर सुदृढ़ता और क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

1.59 रिज़र्व बैंक नए उपयोग मामलों और विशेषताओं को शामिल करते हुए e₹-रिटेल और e₹-होलसेल में चल रहे पायलटों के दायरे और कार्यक्षेत्र का और विस्तार करेगा, तथा पारदर्शिता, ग्राहक सुविधा और दक्षता बढ़ाने के लिए खाता समाहर्ता ढांचे के प्रौद्योगिकीय पहलुओं में सुधार लाएगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक टर्नअराउंड समय, दक्षता और पारदर्शिता

¹⁶ पीआईबी (2025), 'भारत का निर्यात ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंचा', वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, 1 फरवरी।

¹⁷ विनियामक अनुप्रयोग, सत्यापन और अधिकृतीकरण मंच (PRAVAAH), 28 मई 2024 को शुरू किया गया, जो रिज़र्व बैंक से विनियामक अनुमोदन, अधिकृतीकरण और लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक एकीकृत और सुरक्षित पोर्टल है।

से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आधार पर सीमा पार भुगतान पर सीबीडीसी पायलट शुरू करने की संभावना तलाश रहा है।

1.60 वर्ष 2025-26 में पेमेंट-विजन 2025 समाप्त होगा। रिजर्व बैंक एक नए पेमेंट-विजन दस्तावेज का मसौदा तैयार करना शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य पिछले दशक की भुगतान प्रणाली के विकास पर नव-निर्माण करना और इस क्षेत्र में समाधान विकसित करने और उन्हें उपयोग में लाने के लिए भुगतान पारितंत्र में संस्थाओं को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान दिए जाने का होगा। साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की सुविधा के लिए डिजिटल भुगतान के उपयोग पर एक सर्वेक्षण किया जाएगा, जो अधिक समावेशी भुगतान पारितंत्र के लिए आधार तैयार करेगा। घरेलू भुगतान प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीयकरण भी एक प्रमुख प्राथमिकता बनी रहेगी और रिजर्व बैंक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर अन्य देशों के साथ सहयोग की संभावना तलाशना जारी रखेगा।

1.61 डिजिटल भुगतान में वृद्धि जारी है, अतः सुरक्षा बढ़ाने, ग्राहक संरक्षण और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए रिजर्व बैंक की प्रतिबद्धता 2025-26 में बड़ी प्राथमिकताएं बनी रहेंगी। डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की एक योजना बनाई जा रही है, जिसमें भुगतान संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

1.62 रिजर्व बैंक समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और सस्ती बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि, और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। इस दिशा में, रिजर्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच – रिजर्व बैंक इनोवेशन हब) के माध्यम से एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई) के रूप में प्रौद्योगिकी आधारित एक पहल शुरू की

गई है, जिसका उद्देश्य कृषि, डेयरी और एमएसएमई क्षेत्रों में उधारकर्ताओं के लिए टर्नअराउंड समय, लागत और सुविधा के संदर्भ में पहुंच में सुधार करना और दक्षता बढ़ाना है। रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) पर संशोधित मास्टर निदेश जारी किए, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं। इसके अलावा, 2025-26 में वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) की समीक्षा की जाएगी।

1.63 विनियामकीय अनुमोदनों और नागरिक केंद्रित सेवाओं की समयबद्धता में और सुधार लाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नागरिक चार्टर की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 के तहत शिकायत समाधान की गुणवत्ता और गति बढ़ाने के लिए, रिजर्व बैंक इस योजना की समीक्षा करेगा और प्रौद्योगिकी संचालित पहलों को, विशेष रूप से शिकायत प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन पर, कार्य शुरू करेगा। रिजर्व बैंक ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए विनियमित संस्थाओं की आंतरिक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

4. निष्कर्ष

1.64 संक्षेप में, लंबे समय से चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2024-25 के दौरान सुदृढ़ता प्रदर्शित की, जिसे मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचों और सक्रिय नीतिगत उपायों से बल मिला। मुख्यतः इनपुट लागत दबावों में कमी आने, आपूर्ति पक्ष के सक्रिय उपायों और पिछली मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के निरंतर प्रभाव के कारण वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में कमी आई और वह लक्ष्य के करीब पहुंच गई। वित्तीय क्षेत्र की मजबूती, जो बेहतर आरिस्त गुणवत्ता और बैंकों के यथोचित रूप से पूंजीकृत होने में परिलक्षित होती है, ने आर्थिक गतिविधि को और अधिक बढ़ावा दिया। कई वैश्विक चुनौतियों के बीच, भारतीय वित्तीय बाजारों ने समुत्थानशीलता और समयानुकूल प्रदर्शन

किया। बेहतर कर राजस्व प्राप्त और विवेकपूर्ण व्यय प्रबंधन के समर्थन से केंद्र सरकार ने अपने राजकोषीय सुदृढीकरण के प्रयासों को जारी रखा। बाह्य मोर्चे पर, पण्य व्यापार घाटे की भरपाई मजबूत सेवा निर्यात और स्थिर विप्रेषण प्रवाह से हुई, जिससे चालू खाता घाटा एक धारणीय स्तर पर बना रहा।

1.65 भविष्य की ओर देखें तो, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार विखंडन, आपूर्ति

शृंखला व्यवधान और जलवायु-प्रेरित अनिश्चितताएं संवृद्धि की गति को कम करने और मुद्रास्फीति में वृद्धि होने का जोखिम पैदा करती हैं। इसके बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने मजबूत समष्टि आर्थिक आधारस्तंभों, मजबूत वित्तीय क्षेत्र और टिकाऊ संवृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता के बल पर वर्ष 2025-26 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में बने रहने के लिए तैयार है।